



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 कार्तिक , 1944 (श०)

संख्या – 553 राँची, शुक्रवार,

18 नवम्बर, 2022 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

14 नवम्बर, 2022

विषय % जल संसाधन विभाग द्वारा **RIDF-XXVII** के तहत सिकटिया वृहद् सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 45161.01 लाख रुपये (चार सौ इकावन करोड़ इकसठ लाख एक हजार रुपये मात्र) के ऋण आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा कुल स्वीकृत ऋण (45161.01 लाख) का 20% अर्थात् रुपये 9032.202 लाख रुपये (नब्बे करोड़ बत्तीस लाख बीस हजार दो सौ रुपये मात्र) नाबार्ड द्वारा **Mobilization Advance** के रूप में उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

ज्ञापांक : अर्थोपाय (30)-14/2022..585..बजट--राज्य सरकार **RIDF-XXVII** के तहत सिकटिया वृहद् सिंचाई परियोजना का कार्यान्वयन जल संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिसके लिए नाबार्ड के पत्र सं० **NB.JH.SPD/1725/RIDF-XXVIII-Sikatia Mega Lift Irrigation/2022-23**, दिनांक **06.10.2022** द्वारा रुपये **45161.01** लाख की ऋण राशि स्वीकृत है। अतः मंत्रिपरिषद् से प्राप्त स्वीकृति के आलोक में निम्न शर्तों के साथ नाबार्ड से ऋण आहरण करने का निर्णय लिया गया है :-

2. परियोजना की कुल लागत 48435.09 लाख रुपये हैं] जिसमें नाबार्ड से 45161.01 लाख रुपये एवं राज्य संसाधन का हिस्सा (2376.90 + 897.18) = 3274.08 लाख रुपये शामिल हैं।
3. सिकटिया वृहद् सिंचाई परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है] जिसकी प्रति पत्राचार भाग पर रक्षित है।
4. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ऋण राशि का आहरण यथा; अनुसूची। वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में किये जायेंगे।
5. यदि किसी कारणवश प्राक्कलित राशि में विधिसम्मत तरीके से संशोधन होता है] तो जल संसाधन विभाग द्वारा इसकी सूचना नाबार्ड एवं वित्त विभाग को उपलब्ध करायेगी।
6. ऋण के सामान्य एवं विशेष शर्तें नाबार्ड के स्वीकृति पत्र में अंकित हैं। इसका अनुपालन जल संसाधन विभाग द्वारा किया जायेगा।
7. नाबार्ड से ऋण राशि का आहरण प्राप्त करने के लिए योजना का मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रशासी विभाग द्वारा सांस्थिक वित्त प्रभाग] वित्त विभाग के माध्यम से वित्त विभाग] झारखण्ड सरकार को समर्पित किया जायेगा] जिसके आधार पर नाबार्ड से ऋण राशि का आहरण किया जायेगा। ऋण की मूल राशि एवं इसपर देय ब्याज राशि का भुगतान वित्त विभाग द्वारा की जायेगी, जिसके लिए वित्तीय बजट का प्रावधान किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन हेतु नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण राशि (45161.01 लाख) का 20% अर्थात् रुपये 9032.202 लाख रुपये (नब्बे करोड़ बत्तीस लाख बीस हजार दो सौ रुपये मात्र) नाबार्ड द्वारा Mobilization Advance के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराया जाना है।
8. जल संसाधन विभाग NABARD RIDF से संचालित योजना का अपनी website पर प्रारम्भ से अद्यतन की स्थिति संधारित करेगा।
9. चालू (on going) योजना की भौतिक प्रगति एवं वित्तीय प्रगति जल संसाधन विभाग] विभागीय website पर update करेगा।
10. जल संसाधन विभाग निर्माण गुणवत्ता का स्वतंत्र evaluator से भी monitoring करायेंगा तथा विशेष ध्यान देगा एवं इसे भी website पर update करेगा।
11. यह संकल्प विभागीय संलेख संख्या-553/बजट] दिनांक 07.11.2022 पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 10.11.2022 में मद संख्या-15 के रूप में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में निर्गत किया जाता है।

अखौरी शशांक सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।
